Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

कक्षा - 12

स्वतंत्र भारत में राजनीति

अध्याय - 7

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ

भाग - 2

Satyaveer Yadav

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

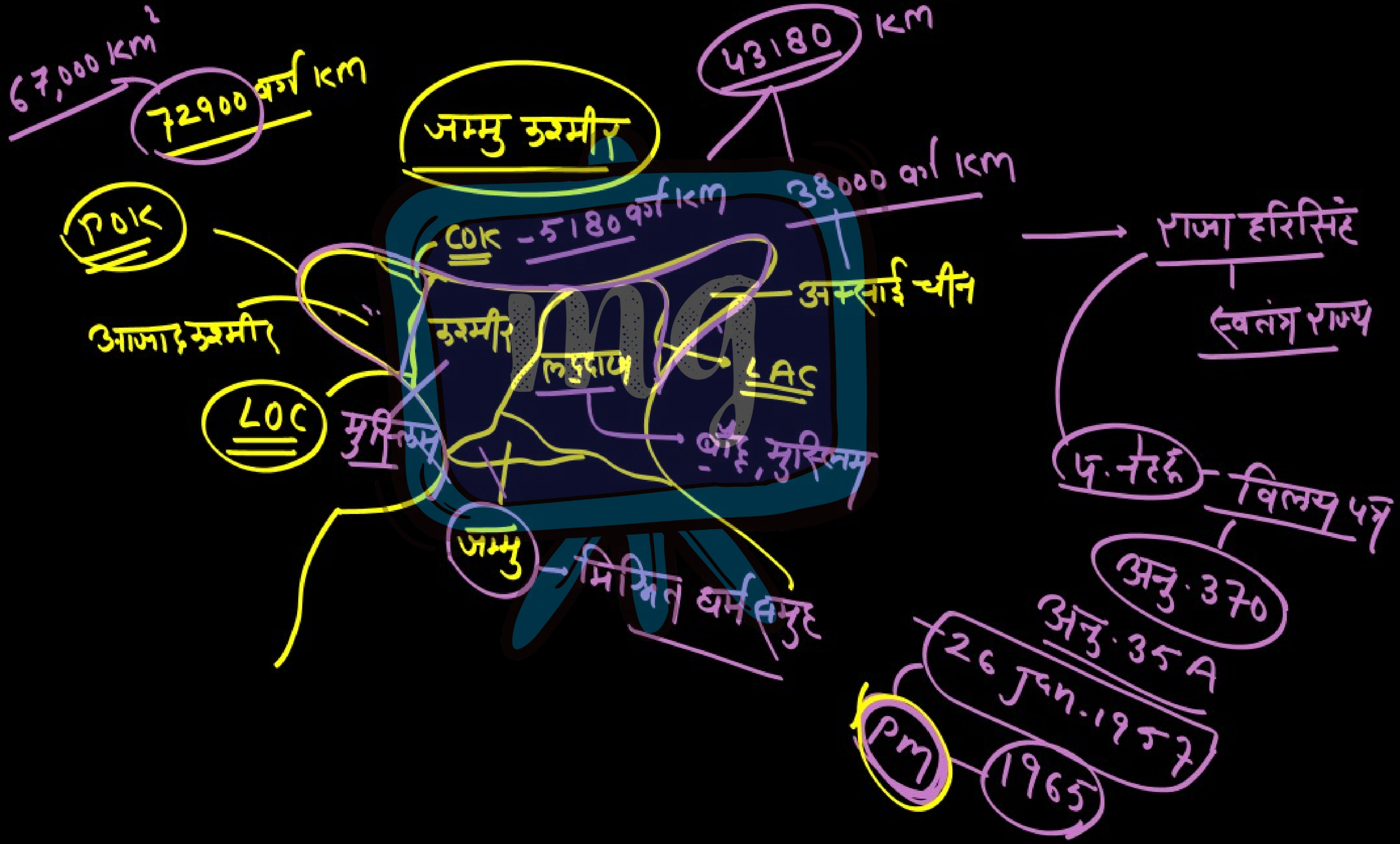

Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

आंतरिक विवाद

कश्मीर को संविधान में विशेष दर्जा

धारा 370 के तहत

संसद द्वारा पारित कानून राज्य में उसकी सहमति के बाद ही लागू

राज्य का अपना संविधान

भारतीय संविधान सारी व्यवस्थाएं यहां लागू नहीं

35A

दो विरोधी प्रतिक्रियाएं

- राज्य के विशेष दर्जे से यह भारत के साथ नहीं जुड़ पाया।
- धारा 370 समाप्त करके को अन्य राज्यों के समान ही होना चाहिए।

- जम्मू–कश्मीर को इतनी भर स्वायत्ता पर्याप्त नहीं।
- भारत सरकार ने जनमत संग्रह के वादे को पूरा नहीं किया।
- धारा 370 के तहत विशेष दर्जा पूरी तरह अमल में नहीं लाया गया।

Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

राजनीति 1948 के बाद

1948 → शेख अब्दुल्ला

- प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद शेख अब्दुल्ला ने भूमि-सुधार की बड़ी मुहिम चलायी। उन्होंने इसके साथ साथ जन कल्याण की कुछ नीतियाँ भी लागू की।
- कश्मीर की हैसियत को लेकर शेख अब्दुल्ला के विचार केन्द्र से अलग - दोनों के बीच मतभेद।
- 1953 में शेख अब्दुल्ला बर्खास्त, नजरबंद।
- शेख अब्दुल्ला के बाद के नेता लोकप्रिय नहीं।
- कांग्रेस के समर्थन के दम पर ही वे राज्य में शासन चला सके।
- राज्यों में हुए विभिन्न चुनावों में धांधली और गड़बड़ी में गंभीर आरोप।

Under CSR Support by ipca Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

1953 से 1974 तक राज्य की राजनीति पर कांग्रेस का असर

- नेशनल कांफ्रेंस कांग्रेस में मिल गई
  - राज्य की सत्ता सीधे कांग्रेस के नियंत्रण में

- 1974 में इंदिरा गांधी व शेख अब्दुल्ला के बीच समझौता
  - शेख अब्दुल्ला बने मुख्यमंत्री
  - नेशनल कांफ्रेंस को फिर से खड़ा किया।
  - 1977 के विधानसभा चुनाव में बहुमत
  - 1982 में शेख अब्दुल्ला की मृत्यु
  - पुत्र फारूख अब्दुल्ला ने संभाली कमान।

- मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला को राज्यपाल ने बर्खास्त किया।
  - कश्मीर में नाराजगी के भाव
  - 1986 में नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस पार्टी में चुनावी गठबंधन
  - लोगों को लगा – केन्द्र राज्य की राजनीति में हस्तक्षेप कर रहा है।

Under CSR Support by ipca Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

विद्रोही तेवर

1987 में विधानसभा चुनाव
→ नेशनल कांफ्रेंस तथा कांग्रेस के गठबंधन को भारी जीत
→ लोगों ने चुनाव में धांधली के आरोप लगाये।

1980 से ही लोगों में प्रशासनिक अक्षमता को लेकर रोष।
→ गुस्सा भड़का – कि केन्द्र के इशारे पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ हेरा–फेरी की जा रही है।

राजनीतिक संकट
→ इस संकट ने राज्य में जारी उग्रवाद के बीच गंभीर रूप धारण किया।
→ उग्रवाद को पाक से नैतिक, भौतिक और सैनिक सहायता
→ 1990 के बाद के समय लोगों को उग्रवादियों और सेना की हिंसा भुगतनी पड़ी।

Under CSR Support by
ipca | Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

विद्रोही तेवरों के बाद

1987 में विधानसभा चुनाव

फारूख अब्दुल्ला के नेतृत्व में नेशनल कांफ्रेंस की सरकार

जम्मू–कश्मीर के लिए क्षेत्रीय स्वायत्ता की मांग

2002 के विधानसभा चुनाव

निष्पक्ष चुनाव

नेशनल कांफ्रेंस को बहुमत नहीं

पीपुल्स डेमोक्रेटिक अलायंस (PDA) और कांग्रेस की गठबंधन सरकार सत्ता में।

Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

अलगाव और उसके बाद

1989 से जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी राजनीति ने सर उठाया।

तीन धाराएं

- कश्मीर को एक अलग राष्ट्र बनाया जाये।
- कश्मीर का विलय पाकिस्तान में हो।
- कश्मीर भारत संघ का हिस्सा रहे लेकिन उसे और स्वायत्ता दी जाये।

- स्वायत्ता की बात जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों को अलग-अलग ढंग से लुभाती है।
- इस क्षेत्र के लोगों की आम शिकायत उपेक्षा भरे बरताव और पिछड़ेपन को लेकर।
- इस जगह से पूरे राज्य की स्वायत्ता की मांग जितनी प्रबल है उतनी ही प्रबल मांग इस राज्य के विभिन्न भागों में अपनी स्वायत्ता को लेकर है।

Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

- शुरूआती सालों से उग्रवाद को लागों को कुछ समर्थन हासिल था लेकिन अब यहां के लोग शांति की कामना कर रहे हैं।
- अलग राष्ट्र की मांग की जगह अब अलगाववादी समूह अपनी बातचीत में भारत संघ के साथ कश्मीर के रिश्ते को पुर्नपरिभाषित करने पर जोर दे रहे हैं।

Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

✍ 5 अगस्त 2019 को केन्द्र सरकार ने संविधान से धारा 370 हटा दी और राज्य का विभाजन दो केन्द्र शासित क्षेत्रों जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के रूप में कर दिया।

2024 – cm

उमर अब्दुल्ला

Under CSR Support by ipca Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

पंजाब

- पंजाब की सामाजिक बनावट विभाजन के समय पहली बार बदली।
- बाद में इसके कुछ हिस्सों से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश बनाये गये, इससे भी पंजाब की सामाजिक संरचना बदली।
- 1966 में पंजाबी भाषी प्रांत का निर्माण हुआ। सिक्खों की राजनीतिक शाखा के रूप में 1920 में अकाली दल का गठन हुआ।
- अकाली दल ने 'पूंजाबी सूबा' के गठन का आंदोलन चलाया।

Under CSR Support by ipca Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

राजनीति संदर्भ

- पंजाबी सूबे के गठन के बाद
  - 1967 और 1977 में अकाली दल ने सरकार बनायी।
  - गठबंधन सरकार
  - अकालियों को स्पष्ट कि इनकी राजनीतिक स्थिति डांवाडोल
    - सिक्ख समुदाय भी जाति/वर्ग के आधार पर बंटा हुआ
    - हिंदुओं के बीच समर्थन नहीं
    - केन्द्र द्वारा कार्यकाल पूरा होने से पहले ही सरकार बर्खास्त
- केन्द्र-राज्य के संबंधों को पुर्नपरिभाषित करने की मांग
- 1970 के दशक में अकालियों के एक तबके ने पंजाब की स्वायत्ता की मांग उठायी।
- 1973 में आनंदपुर साहिब में प्रस्ताव पारित
  - केन्द्र-राज्य के संबंधों को पुर्नपरिभाषित करने की मांग
  - क्षेत्रीय स्वायत्ता
  - सिक्ख कौम की आंकाक्षाओं पर जोर देते हुए सिक्खों के वर्चस्व का ऐलान

Under CSR Support by ipca Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

- आंनदपुर साहिब प्रस्ताव संघवाद को मजबूत करने की बात करता है, लेकिन इसे अलग सिक्ख राष्ट्र अपील की मांग के रूप में भी पढ़ा जा सकता है।
- इस प्रस्ताव का सिक्ख समुदाय पर बड़ा कम असर पड़ा।
- कुछ साल बाद जब 1980 में अकाली दल की सरकार बर्खास्त हो गयी तो अकाली दल ने पंजाब तथा पड़ोसी राज्यों के बीच पानी के बंटवारे के मुद्दे पर आंदोलन चलाया।
- धार्मिक नेताओं के एक तबके ने स्वायत्त सिक्ख पहचान की माँग उठायी।
- कुछ चरमपंथी तबकों ने भारत को अलग होकर 'खालिस्तान' बनाने की वकालत की।

Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

हिंसा का चक्र

- आंदोलन का नेतृत्व नरमपंथी से चरमपंथी तत्वों के हाथों में
- आंदोलन ने सशस्त्र विद्रोह का रूप लिया।

- उग्रवादियों ने स्वर्ण मंदिर को अपना मुख्यालय बनाया।
- स्वर्ण मंदिर एक हथियारबंद किले में तब्दील हो गया।

- जून 1984 में 'ऑपरेशन ब्लू स्टार'। (Thunder)
- स्वर्ण मंदिर में की गयी सैन्य कार्यवाही
- सैन्य अभियान में सरकार ने उग्रवादियों को सफलतापूर्वक मार भगाया।
- स्वर्ण मंदिर को भी क्षति
- सिक्खों की धार्मिक भावनाएँ आहत
- सिक्खों ने इसे धार्मिक–विश्वास पर हमला माना
- इन बातों से उग्रवादी और चरमपंथी ताकतों को बल मिला।

Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

हिंसा का चक्र

31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या

उनके सिक्ख अंगरक्षक द्वारा

बेअंत
सतवंत

ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने के लिए

दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में सिक्ख समुदाय के विरुद्ध हिंसा

2000 से ज्यादा सिक्ख दिल्ली में मारे गये।

कानपुर बोकारो और चांस जैसी अनेक जगहों पर सैकड़ों सिक्ख मारे गये।

कई सिक्ख परिवारों में कोई पुरूष नहीं बचा।

सिक्खों को सबसे ज्यादा दुख इस बात का – सरकार ने स्थिति को सामान्य करने के लिए देर से कदम बढ़ाए।